



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939

No. 79]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

प्रकरण सं. ओआई 23/2017

विषय: बांग्लादेश और चीन जन गण के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "फिशनेट" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जांच।

फा. सं. 14/44/2016-डीजीएडी.—इंडियन फिशनेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे एतदपश्चात एसोसिएशन अथवा याचिकाकर्ता कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात 'प्राधिकारी' कहा गया है), के समक्ष चीन जन गण (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है) से फिशनेट (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए याचिका दायर की है।

2. और यतः प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया यह पाया कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति होने, और कथित पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने के पर्याप्त प्रमाण दिए गए हैं, ताकि पाटनरोधी जांच आरंभ करने को न्यायोचित ठहराया जा सके और प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की जांच शुरू करने तथा नियमावली के नियम-5 के अनुसार घरेलू उद्योग की परिणामी क्षति, तथाकथित पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव का पता लगाने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने की

सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने में पर्याप्त होगा।

3. और यतः प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति होने, और पाटनरोधी जांच शुरू करने को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का अस्तित्व पाया है। प्राधिकारी, तथाकथित पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव का पता लगाने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने में पर्याप्त होगा, की एतद्वारा जांच शुरू करते हैं।

घरेलू उद्योग और आधार

4. संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उद्योग के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने में फिशनेट उत्पादकों की ओर से इंडियन फिशनेट मैनुफेक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा याचिका दायर की गई है।
5. रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, आवेदक के उत्पादन में "घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात" शामिल है। संबद्ध उत्पाद का उत्पादन अधिकांशतः देश में असंगठित क्षेत्र में है। संबद्ध वस्तुओं के अधिकांश भारतीय उत्पादक एसोसिएशन के सदस्य हैं।
6. आवेदक ने प्रमाणित किया है कि संबद्ध देशों से याचिका कंपनियों द्वारा संदर्भित उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता के उत्पादन में भारत में संबद्ध उत्पाद के कुल उत्पादन में "एक प्रमुख अनुपात" शामिल है, आवेदक नियमावली के अभिप्रायः के भीतर घरेलू उद्योग का हिस्सा है और पक्ष से संतुष्ट है। इसलिए, प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्रायः के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और नियमावली के नियम 5(3) की शर्तों के अनुसार, पक्ष के मानदंडों से संतुष्ट है।

संबद्ध उत्पाद

7. वर्तमान याचिका में संबद्ध उत्पाद "फिशनेट अथवा फिशिंग नेट" है।
8. फिशिंग नेट ग्रिड लाइक्स स्ट्रक्चर में बुने गए फाइबर से बना डिवाइस है। फिशिंग नेट आम तौर पर तुलनात्मक रूप से पतले धागे की गांठ लगाकर बने होते हैं। पूर्ववर्ती नेट ग्रासेस, फ्लेक्सेस तथा अन्य फाइब्रश प्लांट सामग्री से बुने होते थे। बाद में कॉटन का प्रयोग किया गया। नायलॉन की तकनीकी विशेषताओं के कारण नायलॉन फिशनेट संपूर्ण विश्व की कुल फिशनेट खपत का 65 से 70 प्रतिशत से अधिक है, जबकि एचपीडीई कुल फिशनेट का 25 से 30 प्रतिशत है, पीपी/पॉलिस्टर कुल वैश्विक मांग का 5 से 10 प्रतिशत है। वर्तमान याचिका में केवल नायलॉन फिशिंग नेट शामिल है – चाहे 100 प्रतिशत ब्लैंडिड हो। ब्लैंडिड के मामले में कार्य क्षेत्र में फिशिंग नेट शामिल है जिसमें भार में 50 प्रतिशत अथवा अधिक नायलॉन युक्त हैं।
9. उत्पाद का समर्पित वर्गीकरण नहीं किया गया है, उत्पाद एचएस कोड 560811 10 के अंतर्गत आयातित किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से उत्पाद के क्षेत्राधिकार को बाध्य नहीं करता।
10. आयात के आंकड़ों का विश्लेषण करने के प्रयोजन से प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस लेन-देन वार आंकड़ों पर विश्वास किया है।

समान वस्तु

11. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा कि आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद तथा संबद्ध देशों से आयातित अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। इन दोनों का एक-दूसरे

के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। आवेदक ने आगे दावा किया है कि ये दो तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस प्रकार इन्हें नियमावली के तहत समान वस्तु माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों/क्षेत्र के मूल की अथवा वहां से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के लिए 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच बांग्लादेश तथा चीन जन गण (जिसे संबद्ध देश कहा गया है) से संबद्ध उत्पाद के तथाकथित पाटन के संबंध में है।

सामान्य मूल्य

13. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतों के संबंध में सरकारी डोमेन में विश्वसनीय सूचना नहीं होने के कारण संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य उत्पादन की लागत के आधार पर कच्चे माल की लागत, उपयोगिताओं की लागत, घरेलू उद्योग की रुपांतरण लागत को ध्यान में रखते हुए, विक्रय, सामान्य और प्रशासन व्यय, औचित्यपूर्ण लाभ आधिक्य को विधिवत रूप से समायोजित करके अनुमानित किया गया है।

निर्यात कीमत

14. आवेदकों द्वारा निर्यात कीमतें डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़े अपनाकर संबद्ध उत्पाद के भारत में भारित औसत आयात कीमत के रूप में दावा किया गया है। सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच एक निष्पक्ष तुलना के लिए व्यापार के उसी स्तर पर दो की तुलना करना आवश्यक है। निर्यात कीमतें सीआईएफ मूल्य हैं जबकि सामान्य मूल्य कारखाना बाह्य स्तर पर होने के कारण समुद्री माल-भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय माल-भाड़ा व्यय तथा पोर्ट व्यय के लिए समायोजित किया गया है।

पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य, कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की तुलना में अधिक है जो दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित की जा रही हैं। पाटन मार्जिन उपरोक्त डिमिनिमस पर अनुमानित किया जाना है।

जांच की अवधि

16. आवेदक द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 (12 माह) है। तथापि, अधिक अद्यतन आंकड़ों के आधार पर अपेक्षित विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी को सक्षम बनाने हेतु प्राधिकारी ने पीओआई अप्रैल, 2015 से सितंबर, 2016 (18 माह) निर्धारित की है। तथापि, क्षति जाँच अवधि में 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जांच की अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातक, भारत में अपने दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

समय-सीमा

18. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए अनुरोध इस जाँच शुरूआत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच शुरूआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और पाटनरोधी उपाय करने की आवश्यकता के बारे में प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में 'गोपनीयता' का दावा किया जाता है तो दो पृथक सेटों (क) गोपनीय अंकित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि) (ख) दूसरा सेट अगोपनीय अंकित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाए। भेजी गई सभी सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर गोपनीय अथवा अगोपनीय स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित किया जाए।
21. गोपनीय अंकित किए बिना सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। गोपनीय रूपांतरण की दो (02) प्रतियां तथा अगोपनीय रूपांतरण की पांच (05) प्रतियां सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाएं।
22. गोपनीयता का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रस्तुत करने वाले को दी गई सूचना के साथ यह कारण उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा कि इस प्रकार की सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकती और/अथवा इस प्रकार की सूचना का संक्षेपण करना संभव नहीं है।
23. अगोपनीय रूपांतरण गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण का प्रतिरूप होना चाहिए और प्राथमिक रूप से जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया जा रहा है, वह सूचीबद्ध अथवा खाली अथवा सारांश की हुई होनी चाहिए। अगोपनीय सारांश अनिवार्यतः गोपनीयता आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के तथ्यों को औचित्यपूर्ण ढंग से समझकर अनुमति हेतु पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीयता सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना सारांश करने के लिए ग्रहणीय नहीं है। उन कारणों का विवरण, जिनसे सारांश करना संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए अनिवार्यतः उपलब्ध कराए जाएं।
24. प्राधिकारी प्रस्तुत जानकारी के स्वरूप की जांच संबंधी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक है अथवा सूचना प्रदान करने वाला सूचना को सार्वजनिक करने का इच्छुक नहीं है अथवा सामान्य रूप में अथवा सार रूप में इसका प्रकटीकरण करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु इस प्रकार की सूचना को मना कर सकता है।

25. किसी तर्कपूर्ण अगोपनीय रूपांतरण अथवा गोपनीयता के दावे संबंधी किसी अच्छे कारण के बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता। प्राधिकारी संतुष्ट होने पर और उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर इस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने के लिए पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइलों का निरीक्षण

26. नियम 6(7) की शर्तों के अनुसार, कोई हितबद्ध पक्षकार ऐसी सरकारी फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत गैर-गोपनीय रूपांतरण हो।

असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

Case No. OI 23/2017

Subject: Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of “Fishing Net” originating in or exported from Bangladesh and China PR.

F. No.14/44/2016-DGAD.—Indian Fishnet Manufacturers Association (hereinafter referred to as ‘association’ or ‘petitioner’) has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of fishnet (hereinafter referred to as the ‘subject goods’) from Bangladesh and China PR (hereinafter referred to as the ‘subject countries’).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the quantum of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

3. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the dumping and ‘injury’ exists to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the quantum of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

4. The petition has been filed by Indian Fishnet Manufacturers Association on the behalf of the fishnet producers in India representing as the domestic industry of the subject goods.

5. As per the evidence available on record, the production of the applicant constitutes “a major proportion” of the domestic production. The production of the product under consideration is largely in the unorganized sector in the country. Majority of the Indian producers of subject goods are members of the association.
6. The applicant has certified that there are no imports of the product under consideration by the petitioner companies from the subject countries. Since the production of the petitioner accounts for “a major proportion” in the total production of the product under consideration in India, the applicant satisfies the standing and constitutes Domestic Industry within the meaning of the Rules. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

7. The product under consideration in the present petition is “Fishnet” or “Fishing Net”.
8. Fishing Nets are devices made from fibers woven in a grid-like structure. Fishing nets are usually meshes formed by knotting a relatively thin thread. Early nets were woven from grasses, flaxes and other fibrous plant material. Later cotton was used. Due to the technical characteristics of Nylon, Nylon fishnet constitutes more than 65-70% of the total fishnet consumption world over. While HPDE is at 25 - 30% of the total fishnets, PP/ Polyester constitute 5-10% of the total demand globally. Present petition includes Nylon Fishing nets only – whether 100% or blended. In case of blended, scope includes fishing nets containing 50% or more Nylon by weight.
9. The product does not have dedicated classification. The product is being imported under HS Code, 560811 10. The customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.
10. For the purpose of analyzing the imports data, the Authority has relied upon transaction wise DGCI&S data.

Like Articles

11. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicant, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The applicant has further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as “like article” under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicants in India as “Like Article” to the subject goods being imported from the subject countries/territory.

Subject Countries

12. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from Bangladesh and China PR (referred to as the “subject countries”).

Normal value

13. The petitioners have submitted that in absence of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject countries, the Normal Value in the subject countries have been estimated on the basis of cost of production; taking into account cost of raw material, cost of utilities and conversion cost of domestic industry, duly adjusted on account of selling, general & administration expenses, plus reasonable profit.

Export Price

14. The export price has been claimed by the applicants as weighted average import price into India of the product under consideration by adopting DGCI&S published data. For fair comparison between the normal value and export price, it is necessary to compare the two at the same level of trade. The export prices being CIF value while the normal values being at ex-factory level, the export prices have been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses and port expenses.

Dumping Margin

15. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margins are estimated to be above de minimis.

Period of Investigation

16. The Period of Investigation (POI) proposed by the applicant is from April 2015 to March 2016 (12 months). However, for enabling the Authority to make required analysis on the basis of more updated data, the Authority has fixed

the POI as April 2015 to September 2016 (18 Months). The injury investigation period will however cover the periods 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 and period of investigation.

Submission of information

17. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street
New Delhi - 110001**

Time limit

18. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation

L. Submission of Information on Non-Confidential basis

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non confidential version must be submitted by all the interested parties.

22. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information

Inspection of Public File

26. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

27. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr.INDERJIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority